प्रतिदिन

सहमति और संशय

भारत, रूस और चीन के विदेशमंत्रियों की सोमवार को नई दिल्ली में हुई बैठक सकारात्मक ही कही जाएगी. इस बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि तीनों देशों ने पहली बार आतंकवाद के खिलाफ समान दृष्टिकोण और एकजुटता का इजहार किया है. भारत की विदेशमंत्री सुषमा स्वराज, चीन के विदेशमंत्री वांग यी और रूसी विदेशमंत्री सर्गेई लावरोव के बीच हुई बातचीत में यों तो आपसी कारोबार समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, पर आतंकवाद का मुद्दा ही प्रमुख रहा. तीनों देशों ने आतंकवाद के हर स्वरूप की निंदा करते हुए मिल-जुल कर इसे रोकने और इसका मुकाबला करने का प्रस्ताव पारित किया है. तीनों देशों के विदेशमंत्रियों की पंद्रहवीं बैठक के बाद जारी साझा बयान में दुनिया के दूसरे देशों का भी आह्वान किया गया है कि वे आतंकवाद के हर रूप की निंदा करें और आतंकवाद को रोकने और उसको माकूल जवाब देने की प्रतिबद्धता दोहराएं. तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर समग्र संधि (सीसीआइटी) को जल्द स्वीकार करने का भी आह्वान किया, ताकि वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा तैयार किया जा सके. सारी बातचीत के लुब्बो-लुआब और साझा बयान से आतंकवाद के मसले पर भारत के रुख की पुष्टि ही हुई है. पर सहमति की सतह के नीचे संशय की मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. यह संशय चीन के अब तक के रवैए की वजह से है.

गौरतलब है कि चीन ने पिछले महीने के शुरू में, जैश ए मोहम्मद का नाम आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल करने की ब्रिक्स घोषणापत्र में जताई गई सहमति के कोई दो महीने बाद, जैश के सरगना मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव को पलीता लगा दिया था. पिछले साल से यह चौथी बार था जब मसूद अजहर का बचाव चीन ने किया. चीन के शियामेन शहर में सितम्बर में हुई ब्रिक्स बैठक में संबंधित देशों का प्रतिनिधित्व उनके राष्ट्राध्यक्षों ने किया था. इसलिए स्वाभाविक ही ब्रिक्स की इस बैठक में बनी सहमति को ज्यादा अहमियत दी गई. लेकिन भारत को जल्दी ही निराश होना पड़ा. आरआइसी यानी रूस, भारत और चीन के विदेशमंत्रियों की ताजा बैठक में बनी सहमति की भी सच्चाई छिपी नहीं रह सकी है. भारत की विदेशमंत्री ने भी, आतंकवादी संगठनों का जिक्र करते समय जैश ए मोहम्मद का नाम नहीं लिया. खुद सुषमा स्वराज ने बताया कि आतंकवाद की चर्चा करते हुए उन्होंने तालिबान, अल कायदा, आइएस और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों की गतिविधियों में बढ़ोतरी के संदर्भ में अपनी बात रखी. लेकिन जैश ए मोहम्मद का नाम क्यों छूट गया? क्या सिर्फ संयोग से हुई चूक थी, या चीन के अब तक के रवैए को ध्यान में रख कर उन्होंने जैश का नामोल्लेख नहीं किया.हर अंतरराष्ट्रीय बैठक या सम्मेलन के मौके पर आतंकवाद से मिल-जुल कर लड़ने की कसम खाई जाती है. यह एक कूटनीतिक चलन-सा हो गया है. यहां तक कि पाकिस्तान भी ऐसे अनेक अंतरराष्ट्रीय संकल्पों में शामिल हो चुका है. खुद इस्लामाबाद में जारी हुए सार्क के एक घोषणापत्र ने दो टूक एलान किया था कि सार्क का कोई भी सदस्य देश आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा. सार्क में सर्वसम्मति से पारित इस संकल्प के बरक्स हकीकत क्या रही है, दुनिया जानती है, और भारत तो उसका भुक्तभोगी ही है. इसी तरह का विरोधाभास अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई में भी दिखता है. अमेरिका की अगुआई वाले आतंकवाद विरोधी अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में पाकिस्तान भी शामिल रहा है. दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर देश यानी चीन का रवैया जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर के मामले में हम कई बार देख चुके हैं. आतंकवाद विरोधी अंतरराष्ट्रीय रणनीति की अनेक खामियां हो सकती हैं, पर सबसे बड़ी खामी है दोहरा मापदंड और चुनिंदा कार्रवाई. यह खामी ही आतंकवाद विरोधी अंतरराष्ट्रीय संकल्पों की राह की सबसे बड़ी बाधा है.

एक करेन्सी...बिटक्वॉइन

जानकारी में ही बचाव

कुछ वर्ष पहले 2013 में अमेरिका में ऑनलाइन ड्रग माफिया से 1.44 लाख बिटकाइन एफबीआई ने जब्त किए थे. आज बिटकाइन सुरसा का रूप धारण कर चुका है और एक आम निवेशक को इससे दूर रहने की सलाह ही उचित सलाह है. रिजर्व बैंक और बड़े निवेश सलाहकारों की बात को ही माना जाना चाहिये.

बिटकाइन एक डिजिटल खदान है, जिस तक पहुंचने के लिए 'खुल जा सिम सिम' टाइप का एक हैश प्रोग्राम है जो हर बार बदल जाता है. यह एक तिलिस्म है और यही इसका आकर्षण भी है. इस कठिनता के चलते बिटकाइन की सप्लाई नियंत्रित होती है. यहां कोई केंद्रीय बैंक नहीं है, जिसे मुद्रास्फीति या आर्थिक विकास देखना हो. यह भी एक चिंता का विषय है. अभी कुछ समय पूर्व तक हम देशों के मध्य 'करेंसी वार' की बात कर रहे थे और अचानक से बिटकाइन एक भस्मासुर के रूप में प्रकट हो गया.

बिटकाइन को लेकर पूरे विश्व में संदेह का माहौल है. चीन के बाद भारत में भी रिजर्व बैंक ने चिंता जाहिर की है. बिटकाइन एक डिजिटल करेंसी है, जो व्यक्ति से व्यक्ति के बीच लेन-देन का डिजिटल साधन है. बेसिक रूप में समझने के लिए 'पेमेंट वॉलेट' से किया गया पेमेंट एक तरह से ऐसा ही लेन-देन है. आपके वॉलेट में रखा हुआ पैसा रुपये के साथ बराबरी में फिक्स है मगर वो रुपया नहीं है, जब तक की वो वापस बैंक अकाउंट में न चला जाए. वॉलेट से आपको अपने अकाउंट में या अपने अकाउंट से वॉलेट में डालना होता है. इस डिजिटल करेंसी को वही स्वीकार कर सकेगा, जिसके पास खुद उस वॉलेट का अकाउंट हो इस सिस्टम को 'पीयर टू पीयर' कहा जाता है.

प्राचीन काल में जब लेन-देन में करेंसी को प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, उस समय 'बार्टर सिस्टम' था. बार्टर सिस्टम में कोई बिचौलिया नहीं होता था. आज बैंक करेंसी इशू करते हैं और उनकी भूमिका बिचौलिये की है. बैंक करेंसी को छापने एवं उसको निर्गमित एवं नियमित करने के एवज में कमीशन लेता है, जो नजर तो नहीं आता पर कहीं न कहीं मनी सप्लाई में जुड़ जाता है अब यदि हम और आप आपसी लेन-देन के समायोजन को किसी ऐसी वस्तु से करें जो भौतिक रूप में न हो कर आभासी रूप में हो तो बिचौलिये की आवश्यकता ही नहीं रहेगी.

बात फिजिकल या डिजिटल की नहीं है. बात है उसके लिए गारंटी देने वाली अथॉरिटी की. बिटकाइन को जारी करने वाली कोई अथॉरिटी नहीं है. इसकी जिम्मेदारी बिटकाइन सिस्टम से जुड़े हुए लोगों की है, जो उस हर लेन-देन को रिकॉर्ड करते हैं और उसके एवज में फीस के तौर पर कुछ हिस्सा बिटकाइन का प्राप्त करते हैं. इसके अलावा बिटकाइन का उत्खनन भी किया जा सकता है. जैसे सोने का खनन होता है. मानों इधर एक डिजिटल खदान है, जिस तक पहुंचने के लिए 'खुल जा सिम सिम' टाइप का एक हैश प्रोग्राम है जो हर बार बदल जाता है. यह एक तिलिस्म है और यही इसका आकर्षण भी है.

इस कठिनता के चलते बिटकाइन की सप्लाई नियंत्रित होती है. यहां कोई केंद्रीय बैंक नहीं है, जिसे मुद्रास्फीति या आर्थिक विकास देखना हो. यह भी एक चिंता का विषय है. अभी कुछ समय पूर्व तक हम देशों के मध्य 'करेंसी वार' की बात कर रहे थे और अचानक से बिटकाइन एक भस्मासुर के रूप में प्रकट हो गया. इस समस्या से अलग-अलग राष्ट्र अलग-अलग तरह से निपट रहे हैं. रूस ने इसको मान्यता दी है, वो इसे डॉलर के आधिपत्य को चुनौती के रूप में देख रहा है. चीन ने इसके खिलाफ स्टैंड लिया है क्योंकि वो इसे कहीं न कहीं एक पारदर्शी व्यवस्था मान रहा है.

यह विचित्र लगेगा मगर बिटकाइन नितांत अपारदर्शी व्यवस्था नहीं है. इससे अधिक अपारदर्शिता कैश एवं गोल्ड में है. ऐसा जरूर है कि अवैध लेन-देन के लिए बिटकाइन एक पसंदीदा माध्यम है क्योंकि इसे काफी समय तक बैंकिंग व्यवस्था से दूर रखा जा सकता है. भारत में बिटकाइन की मान्यता को लेकर भ्रम की स्थिति बरकरार है. रिजर्व बैंक का मानना है कि किसी भी ऐसी चीज को रोक कर नहीं रखा जा सकता जिसका समय आ गया हो, मगर उसकी चिंता है बिटकाइन में अवैध रूप से हो रही सट्टेबाजी. भारत का इतिहास है कि यहां तो इस बात पर भी सट्टा लगा लिया जाता है कि बारिश में पतनाला कितनी दूर तक जाएगा. इस अवैध व्यापार को रोकना सिर्फ जागरुकता से ही हो सकता है.

चिंता है पोंजी स्कीम के रूप में बिटकाइन अर्थव्यवस्था में शामिल न हो जाए. आजकल जिस तरह के उतार-चढ़ाव देखने को आ रहे हैं, बिटकाइन में अवश्य ही इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. निवेशक प्राइवेट इंतजामों के द्वारा इस तरह के निवेश में कहीं न कहीं ट्रैप हो सकते हैं. बिटकाइन का न कोई रेगुलेटर है न ही उसके मूल्य का कोई आधार. निवेश की दुनिया के बादशाह माने जाने वाले वारेन बफेट बिटकाइन को एक निवेश के रूप में अच्छा नहीं समझते और इसको एक बबल बताते हैं. कमोडिटी के विश्व प्रसिद्ध इन्वेस्टर/विश्लेषक जिम रोजर्स इसको बुलबुला मानते हैं. 'जेपी मॉर्गन चेस' के सीईओ जिमी दिमोन ने तो बिटकाइन को फ्रॉड ही करार दिया है.

हाल ही में रिजर्व बैंक ने तीसरी बार सचेत किया है कि बिटकाइन को या किसी भी वर्चुअल करेंसी को कोई मान्यता प्रदान नहीं की गई है और इनमें किसी भी प्रकार की डीलिंग करने वाला खुद इसके लिए उत्तरदायी होगा. रिजर्व बैंक ने अपनी चेतावनी में पांच बातें प्रमुखता से बताई हैं: एक डिजिटल करेंसी को डिजिटल रूप में रखा जाता है तो वो हैकिंग और वायरस अटैक की जद में आ सकती है. दूसरी बात इसकी कोई केंद्रीय एजेंसी नहीं है जो इसको कंट्रोल करे. तीसरी बात है, कीमत में उतार-चढ़ाव निवेशक के लिए घातक हो सकता है. इसमें सट्टेबाजी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. चौथी बात है कि बिटकाइन जैसे 'क्रिप्टो मुद्रा' जिन एक्सचेंज में ली-दी जा रही हैं, उनका नियंत्रण जिन देशों में है उनके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है. अंतिम बात है बिटकाइन का अपराध जनित लेन-देन में उपयोग हो रहा है और इसमें निवेश करने से एंटी मनीलॉन्ड्रिंग एवं टेरर फंडिंग के कानूनों का उल्लंघन कब और कितनी मात्रा में हो जाए इसका अनुमान लगाना मुश्किल है.

बिटकाइन के दाम में इस साल एक हजार प्रतिशत वृद्धि दर्ज की जा चुकी है. आज बिटकाइन का कुल सर्कुलेशन मूल्य लगभग 190 बिलियन डॉलर है, जो कि न्यूजीलैंड जैसे देश की जीडीपी से भी अधिक है. विश्व के दो बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक 'गोल्डमन' और 'यूबीएस' की कुल परिसंपत्तियां भी बिटकाइन की कुल मूल्य से कम है. अगर ये बुलबुला है, जैसी की आशंका जाहिर की जा रही है, तो यह आइडिया जो कि 2008 के क्राइसिस के कारण प्रकाश में आया था, खुद में उससे बड़ा क्राइसिस का कारण बन सकता है.

कुछ वर्ष पहले 2013 में अमेरिका में ऑनलाइन ड्रग माफिया से एक लाख चवालीस हजार बिटकाइन एफबीआई ने जब्त किए थे. आज बिटकाइन सुरसा का रूप धारण कर चुका है और एक आम निवेशक को इससे दूर रहने की सलाह ही उचित सलाह है. रिजर्व बैंक और बड़े निवेश सलाहकारों की बात को ही माना जाना चाहिये.

आर. बी. मेनन.

इंटरनेशनल मीडिया

पीएमएलएन की नई चुनौती

नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पांच और नेताओं के इस्तीफे के बाद पार्टी में टूट की आशंकाएं फिर जन्म लेने लगी हैं. खास बात ये कि सामान्य बात रही है. आश्चर्य नहीं कि तमाम दबावों के बावजूद पीएमएलएन की इस मजबूती को देश के पुख्ता होते लोकतंत्र की निशानी माना जा रहा था. पार्टी

DAWN

इस्तीफे उस अध्यात्मिक नेता को सौंपे गए हैं, एक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ टिप्पणी करने वाले पंजाब के कानून मंत्री की बर्खास्तगी मांगने के अभियान में जिनकी खास भूमिका रही है. खास यह भी कि सारे इस्तीफे फैसलाबाद में आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान सौंपे गए जहां पीएमएलएन सरकार के अस्तित्व के लिए बढ़ते खतरों की बढ़-चढ़कर बात की गई. इस बात पर भी जोर दिया गया कि अब किस तरह धार्मिक नेता ही इसे किसी नए अंजाम पर ले जा सकते हैं. सरकार पर ताजा हमला उस तैयारी का हिस्सा ज्यादा लगता है, जब सरकार को इतना बदनाम कर दिया जाए कि बर्खास्तगी के अलावा कोई विकल्प न रहे.

वैसे भी पीएमएलएन का नवाज जैसे अपने नेता की बर्खास्तगी के बावजूद पार्टी के रूप में बचे रहना महत्वपूर्ण है, वरना अतीत में तो थोड़ी-थोड़ी दुश्वारियों में भी पार्टियों का टूटना या अंतर्कलह का शिकार हो जाना नेतृत्व ने भी इसमें कोई कोताही नहीं बरती, लेकिन सारी मजबूती के बावजूद यह भी उतना ही सच है कि पार्टी अब भी तमाम चुनौतियों से जूझ रही है. इधर संयुक्त मोर्चा खड़ाकर इसे शिकस्त देने की कोशिशों में जबर्दस्त इजाफा आया है और अतीत में झांकें तो ऐसे हालात में समान हित के नाम पर नाराज और अलग-थलग पड़ चुके दलों और नेताओं के एक मंच पर आते देर भी नहीं लगती. पीएमएलएन इसे समझ रही है और हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है. उसके कुछ खास नेता विपक्षी एकता की संभावनाओं को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं. पीएमएलएन ने राजनीतिक विरोधियों पर इधर जैसी आक्रामकता दिखाई है, उसमें इसे सफलता मिल सकती है, पर बेहतर यही होगा कि पार्टी अपने खिलाफ एक नहीं, कई नए मोर्चे देखने के लिए खुद को तैयार कर ले. दीर्घकालिक राजनीतिक अस्तित्व के लिए यह तैयारी बहुत जरूरी है. **डॉन, पाकिस्तान.**

प्रतिदिन

कड़वा सच

एक फकीर कहीं जा रहे थे. रास्ते में उन्हें एक सौदागर मिला, जो पांच गधों पर बड़ी-बड़ी गठरियां लादे हुए जा रहा था. गठरियां बहुत भारी थीं, जिसे गधे बड़ी मुश्किल से ढो पा रहे थे. फकीर ने सौदागर से प्रश्न किया- इन गठरियों में तुमने ऐसी कौन-सी चीजें रखी है, जिन्हें ये बेचारे गधे ढो नहीं पा रहे हैं. सौदागर ने जवाब दिया- इनमें इंसान के इस्तेमाल की चीजें भरी हैं. उन्हें बेचने मैं बाजार जा रहा हूं. फकीर ने पूछा, अच्छा, कौन-कौन सी चीजें हैं, जरा मैं भी तो जानू. सौदागर ने कहा- पहला गधा अत्याचार ले जा रहा है. कौन खरीदेगा इसे? सौदागर ने कहा, इसके खरीदार हैं राजा-महाराजा और सत्ताधारी लोग. काफी ऊंची दर पर बिक्री होती है. दूसरी गठरी अहंकार से लबा-लब भरी है और इसके खरीदार हैं पंडित और विद्वान. तीसरे गधे पर ईष्या की गठरी लदी है और इसके ग्राहक हैं वे धनवान, जो एक-दूसरे की प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर पाते. इसे खरीदने के लिए तो लोगों का तांता लगा रहता है. चौथी गठरी में बेईमानी भरी है और इसके ग्राहक हैं वे कारोबारी, जो बाजार में धोखे से की गई बिक्री से काफी फायदा उठाते हैं. इसलिए बाजार में इसके भी खरीददार तैयार खड़े हैं. फकीर ने पूछा- अंतिम गधे पर क्या लदा है? सौदागर ने जवाब दिया- इस गधे पर छल-कपट से भरी गठरी रखी है और इसकी मांग उन औरतों में बहुत ज्यादा है जिनके पास घर में कोई काम-धंधा नहीं है और जो छल-कपट का सहारा लेकर दूसरों की लकीर छोटी कर अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश करती रहती हैं. वे ही इसकी खरीदार हैं. तभी महात्मा की नींद खुल गई. इस सपने से उन्हें अपने कई प्रश्नों का उत्तर मिल गया था.

नेटीजन

डॉक्टरों की लापरवाही

नॉर्वे में डॉक्टर अगर गलती करते हैं, तो जिम्मेदारी सरकार लेती है, वही इसकी भरपायी करती है.

'मेडिकल नेग्लीजेन्स' के लिए अलग-अलग देशों में अलग व्यवस्थाएं हैं. भारत में कॉरपोरेट दुनिया के लगभग सभी चिकित्सक सालाना 10-15 लाख से करोड़ रुपये तक का बीमा कराते हैं. मैंने भी करा रखा था. अमेरिका व निजी स्वास्थ्य व्यवस्था वाले अन्य देशों में भी है. मुझसे भी गलतियां हुई हैं, खासकर शुरुआती वर्षों में. अब भी होती हैं. इनके ग्रेड भी अलग-अलग हैं. कुछ में बस थोड़ी मायूसी होती है, कुछ ऐसी कि दिल में शूल बनकर बैठ जाती हैं, जो कभी नहीं निकलते. सोचता हूं कि मैंने क्या खाक पढ़ा, खाक सीखा, जो यह गलती कर बैठा. उसके बाद दो-तीन दिन घर-ऑफिस सब अवसादमय रहता है. फिर पूजा-पाठ करके सोचता हूं कि चलो, आगे गलती नहीं करूंगा, और फिर साल-दो साल बाद एक खास थकान भरे पल में 'ब्लंडर' हो जाता है.

गलतियां हर तरह के डॉक्टर से होती हैं. जब नॉर्वे में गलती होती है, तो वहां सरकार जिम्मेदारी लेती है. वही भरपायी करती है. वह कहती है कि इस डॉक्टर को 'ऑथराइजेशन' या लाइसेंस हमने सभी मानकों पर खरा पाकर ही दिया था. और यह पहली गलती है. तीन ऐसी गलतियां होने पर हम लाइसेंस रद्द कर सकते हैं. पर वे गलतियां ऐसी हों, जो डॉक्टर के स्तर के ज्ञान व अनुभव के हिसाब से गलत हो, और उससे मृत्यु या समकक्ष हानि हुई हो. **डॉ. प्रवीण झा की फेसबुक वॉल से.**

सुविचार

इंसान सोचता है कि भगवान है या नहीं..
लेकिन..ये कभी नहीं सोचता कि मैं इंसान हूँ या नहीं.

प्रतिवाद

हिन्दुत्व और राहुल

जिन लोगों ने भी राहुल के सोमनाथ मन्दिर में दर्शन पर सवाल उठाए हैं, उन्हें आत्मचिन्तन करना चाहिए. स्वयं से पूछना चाहिए कि कहीं वे संकीर्ण धार्मिक सोच के तो शिकार नहीं हैं, उस शानदार हिन्दुत्व से दूर नहीं है, जो सभी मतों-विश्वासों का खुले दिल से स्वागत करता है.

राहुल गांधी के सोमनाथ मंदिर में दर्शन और दर्शनार्थियों के लिए रखी गई पंजिका में उनके नाम की प्रविष्टि पर कुछ लोगों ने हिन्दुत्व आधारित उनकी पहचान पर उंगली उठाई है. इस मामले में राहुल को भी वही सब देखना पड़ा है, जैसा उनके दादा फिरोज गांधी और दादी इंदिरा गांधी को मार्च, 1942 में अपनी सगाई के समय भोगना पड़ा था आलोचना, तिरस्कार और आक्षेप.

इस विवाह की निंदा कुछ भ्रमित लोगों ने फिरोज गांधी के धर्म के आधार पर की थी, जो फारसी धर्म को मानने वाले थे. गांधीजी इस तरह की बातों से बेहद दुखी थे उन्होंने इस बाबत 2 मार्च, 1942 को एक लेख इन्दिरा नेहरूज अंगेजमेंट' लिख.यह लेख 'कलक्टिड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी' के वॉल्यूम 82 में देखा जा सकता है. गांधी जी ने अपने लेख में इस बात का उल्लेख किया है कि 'समय के साथ ऐसे संबंध प्रगाढ़ होते चले जाते हैं, जो समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं.' लिखा था कि अभी हम परस्पर सहिष्णुता के उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन..जैसे-जैसे सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता बढ़ेगी वैसे-वैसे ऐसे विवाहों का स्वागत होने लगेगा.' दरअसल, महात्मा गांधी ने उस लेख में प्रतिपादित किया था कि, 'कोई संकीर्ण धर्म जो तार्किक नहीं है, भविष्य के उस समाज के सामने नहीं टिका रह पाएगा जो मूल्य और प्रकृति के मद्देनजर धन-दौलत, परिवेश-विरासत या जन्म के बजाय प्रतिभा-योग्यता से संचालित होगा.'

जहां 1940 के चालीस के दशक में इन्दिरा नेहरू और फिरोज गांधी को धर्म के आधार पर गुस्से का सामना करना पड़ा था, तो इक्कीसवीं सदी के भारत में उनके पौत्र को अपने विश्वास और धार्मिक पहचान को लेकर शरारती सवाल का सामना करना पड़ रहा है. अपने लेख में गांधी जी ने स्पष्ट कहा था, 'हिन्दुत्व की मेरी अवधारणा में हिन्दू कोई संकीर्ण मजहब नहीं है. यह प्राचीन काल से जारी महान क्रांतिकारी प्रक्रिया रही है, और पारसी, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्मों के साथ ही नानक और अन्य धर्माचार्यों, जो याद पड़ते हों, की शिक्षाओं को बढ़कर स्वीकारती है.

जिन लोगों ने भी राहुल के सोमनाथ मन्दिर में दर्शन पर सवाल उठाए हैं, उन्हें आत्मचिन्तन करना चाहिए. स्वयं से पूछना चाहिए कि कहीं वे संकीर्ण धार्मिक सोच के तो शिकार नहीं हैं, उस शानदार हिन्दुत्व से दूर नहीं है, जो सभी मतों-विश्वासों का खुले दिल से स्वागत करता है. दरअसल, राहुल का कहा जाना कि वे भगवान शिव के उपासक हैं, नेहरू के उन उद्गारों के अनुरूप है, जो उन्होंने तारापुर परमाणु संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करते हुए व्यक्त किए थे. जरूरी है कि संकीर्णता को परे धकेला जाए. धार्मिक स्थल पर दर्शनार्थियों के धर्म या विश्वास को व्यापक हिन्दुत्ववादी सोच के बरक्स देखा जाना चाहिए. इसी सोच के चलते आजादी के संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय नेतृत्व को नया दृष्टिकोण मिला था, जिससे धर्मनिरपेक्ष मूल्य मजबूत हुए और भारत का विचार घनीभूत हुआ.

सत्यनारायण साहू.

प्रतिदिन अखबार

यह पत्र मालिक, प्रकाशक, सम्पादक नानक आहूजा द्वारा देविका वेब प्रिंटर्स, राजापेठ, अमरावती से मुद्रित कर 'प्रतिदिन अखबार' कार्यालय, देविका परिसर, ब्राह्मण सभा के पीछे, दरोगा प्लॉट, राजापेठ, अमरावती 444 606 से प्रकाशित किया है. फोन-0721-2560155/56/57/58 फैक्स-0721-2677708 E-mail :- pratidinnews@gmail.com
'प्रतिदिन अखबार' में प्रकाशित होनेवाले विभिन्न लेख, पत्र, साहित्य, लेखकों, कवियों आदि के विचारों या तथ्यों पर आधारित होते हैं. इन लेखकों के विचारों अथवा तथ्यों से संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है. संपादक पर मात्र सम्पादकीय लेखों का ही दायित्व है. संपादक-नानक आहूजा, समाचार संपादक-प्रवीण आहूजा.